दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 25 फरवरी 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 149

प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ वर्चुअल कार्यक्रम में बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में 34 हजार 427 करोड़ रुपए की योजना का किया लोकार्पण-शिलान्यास

- देश के विकास में छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान, विकसित छत्तीसगढ़ से ही होगा विकसित भारत का सपना पूरा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्ध, छत्तीसगढ़ को बना रहे सशक्त-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम-केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर
- छत्तीसगढ़ भी बनेगा विकसित राज्य-वित्त मंत्री ओपी चौधरी

रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रदेश में 34 हजार 427 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इनमें 18 हजार 897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15 हजार 530 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। रायगढ़ जिला मुख्यालय के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग कृष्ण पाल गुर्जर एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान है। विकसित छत्तीसगढ़ से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान हैं। प्रतिभाशाली नौजवान हैं और प्रकृति का खजाना है। यहां विकसित होने की सारी संभावना मौजूद है। आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर बनेंगे। आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था है जिससे रात में आसपास के लोगों को बिजली मिल सकेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जा चुका है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की गारंटी मैंने दी थी। डबल इंजन सरकार ने यह गारंटी पूरी कर दी है। गरीबों के घर पहले नहीं बन पा रहे थे। अब हमारी सरकार गरीबों के घर बनाने तेजी से काम कर रही है। हर घर जल की योजना, इसे भी पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बडिय़ों की जांच का आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना की बधाई देता हूँ इससे लाखों महिलाओं को लाभ होगा। हम जो कहते हैं वो कर के दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।

रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को संवारने का काम तेजी से हो रहा है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि हमारी सरकार आने पर सुशासन स्थापित करते हुए नागरिकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लायेंगे। इसके परिपालन में सरकार ने पहले ही दिन से ही प्रधानमंत्री की गारंटियों पर अमल शुरू कर दिया गया। 18 लाख परिवारों को पक्का आवास देनेए किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान करने, 3100 रुपए कुंविटल के भाव से और 21 कुंविटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने, विवाहित माताओं-बहनों को हर महीने 1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू करने जैसी अनेक गारंटियों को हम पूरा कर चुकें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरे मनोयोग के साथ अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य स्वयं के सामने रखा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग कृष्ण पाल गुर्जर ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के क्षेत्र में अभूत पूर्ण सुधार हुआ है, आज बिजली के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। सबको 24 घंटे सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। आज इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर चरण एक परियोजना अंतर्गत आज 1600 मेगावाट की दो इकाइयों को देश को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही चरण दो परियोजना अंतर्गत दो परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इन दोनों परियोजनाओं से देश को कम लागत में बिजली प्रदान कराई जाएगी। इस परियोजनाओं में 31 हजार 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिससे 24 घंटे विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना की स्थापना से देश में बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने निर्बाध बिजली आपूर्ति की लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से जितनी बिजली पैदा होगी। उसकी आधी छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित होगी। इस परियोजना से रोजगार की भी अवसर उत्पन्न होगी साथ ही देश के अन्य राज्यों में बिजली प्रदाय की स्थिति में सुधार होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा हैं। आज देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए सभी दर्शनीय स्थलों को हाईवे के साथ जोड़ा जा रहा है।

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक हम अमृत काल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जब आजादी का 100 वर्ष पूर्ण होगा, उस दिन भारत विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। जहां बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल कॉलेज जैसी मूलभूत सुविधाएं परिपूर्ण होगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने का संकल्प है, जिसके लिए हम विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहे है।

इस अवसर पर सचिव भारत सरकार विद्युत मंत्रालय पंकज अग्रवाल, संयुक्त सचिव भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय पियूष सिंह, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायगढ़ पूनम सोलंकी, गुरूपाल भल्ला, विजय अग्रवाल, विवेक रंजन सिन्हा, श्रीकांत सोमावार, जगन्नाथ पाणिग्राही, सुभाश पाण्डेय, मुख्य प्रबंध निदेशक एनटीपीसी गुरदीप सिंह, निदेशक वित्त एसईसीएल निवासन, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, आयुक्त नगर पालिक निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, निदेशक परियोजना एवं प्रचालन एनटीपीसी के.एस.सुंदरम आदि उपस्थित रहे।

रायगढ़ में बनेगा नालंदा परिसर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जन सामान्य को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ जिले के शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी हेतु उनकी इच्छानुरूप रायगढ़ जिले में नालंदा परिसर बनेगा। इसी प्रकार एक करोड़ रुपए का महतारी सदन के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है।

केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने विभागीय स्टॉल का भ्रमण कर पात्र हितग्राहियों को किया लाभान्वित

केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग कृष्ण पाल गुर्जर एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में लगाये विभागीय स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर आयुष विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नगर पालिक निगम, ग्रामोद्योग विभाग, रायगढ़ पुलिस, रेशम विभाग, खाद्य विभाग, पशुधन विकास, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एनटीपीसी लिमिटेड, एसईसीएल ने अपने विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए स्टॉल लगाये थे।

महत्वपूर्ण एवं खास

एशियाई खेलों में सशस्त्र बलों के पदक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत सितंबर-अक्टूबर में चीन के हांगझू में आयोजित 19 वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। एशियाई खेलों के साथ-साथ एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये का नकद इनाम मिलेगा।सशस्त्र बलों के अनेक एथलीटों ने इन खेलों में देश को गौरवान्वित किया था। रक्षा मंत्री ने उनकी वापसी पर उन्हें सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने सात पैरा एथलीटों सहित 45 पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की भी मंजूरी दी थी। इन 45 एथलीटों ने एशियाई खेलों में 09 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक और एशियाई पैरा खेलों में 01 स्वर्ण, 04 रजत और 02 कांस्य पदक जीते। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से पहली बार घोषित यह वित्तीय प्रोत्साहन इन एथलीटों को पेरिस ओलंपिक-2024 की क्वालीफाइंग स्पर्धाओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

दिल्ली में झपटमारों ने चाकू गोदकर की एक शख्स की हत्या

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्वी दिल्ली में चार अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मारे जाने से 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपी उसका बैग और मोबाइल फोन लेकर भाग गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान मंडावली निवासी नरेंद्र के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि को मंडावली पुलिस स्टेशन में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) कॉल प्राप्त हुई, इसमें कॉलर ने कहा कि वह अपने दोस्त नरेंद्र के साथ सीएनजी गैस स्टेशन, आईपी एक्सटेंशन के सामने डीडीए पार्क में शराब पीने गया था।

एसटीएफ की बड़ी कार्यवाई : बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार- भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद

पटना (आरएनएस)। बिहार के अरवल जिले में बिहार पुलिस, बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ के संयुक्त अभियान में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और भारी मात्रा में हथियार और उपकरण जब्त किए गए। अरवल के पुलिस अधीक्षक विद्या सागर ने कहा कि छापेमारी के दौरान 9 हथियार कारीगरों और दो महिलाओं सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, फिनिशिंग मशीन, एक खराद मशीन और कच्चा माल भी जब्त किया गया।

अरवल पुलिस को कोलकाता एसटीएफ से मिनी गन फैक्ट्री के बारे में इनपुट मिला था। एसपी ने कहा, हमें पता चला था कि जिले के करपी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राधे बिगहा गांव में नागेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुकेश पटेल के घर में एक मिनी बंदूक फैक्ट्री चल रही थी। हमने एसडीपीओ-सदर राजीव रंजन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है। बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ के जवानों ने छापेमारी की। हमने 9 हथियार कारीगरों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के मुंगेर जिले के हैं।

जांच के दौरान पता चला कि नागेंद्र कुमार सिंह का बेटा सुमित कुमार सिंह और भतीजा रौशन कुमार सिंह उर्फ लड्डू बंदूक फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने छापेमारी के दौरान नागेंद्र कुमार सिंह, उनके बेटे सुमित कुमार सिंह, भतीजे रौशन कुमार सिंह, पत्नी दुर्गा देवी और रौशन की पत्नी आरती कुमारी के अलावा 9 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार कारीगरों की पहचान सुनील कुमार दास, दशरथ शाह, पंकज कुमार, नंदू चौधरी, राहुल कुमार, विशाल कुमार, संजय कुमार शाह, आशीष कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार के रूप में की गई। संयुक्त टीम ने 6 अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 6 आंशिक रूप से निर्मित, अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 6 पिस्तौल बॉडी, 7 पिस्तौल स्लाइडर, 6 बैरल, 7.65 बोर के 7 जीवित कारतूस, एक लेथ मशीन, एक ड्रिल मशीन, 3 इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, 3 ग्राइंडिंग कटर और घर से अन्य कच्चा माल और मशीनरी भी जब्त किए।

हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार, पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश

नई दिल्ली (आरएनएस)। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी। हल्द्वानी पुलिस के मुताबिक, ये गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। मलिक का बगीचा अब्दुल मलिक का ही था, जहां अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन गया था। इसके बाद हिंसा हुई थी।

अब्दुल मलिक 8 फरवरी को भडक़ी हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था। उस पर मलिक का बगीचा के अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम के खिलाफ भीड़ को उकसाने और उन पर जानलेवा हमला कराने का आरोप है। इस मामले में अब्दुल मलिक के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। अब उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह दावा अब्दुल मलिक के वकीलों ने किया है।

अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका में अपील की गई है कि घटना के दिन अब्दुल मलिक यहां नहीं थे। इसी याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता भी इसमें लिखा गया था, जो दिल्ली का था। बताया जा रहा है कि इसी आवेदन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उस पते पर पहुंची। वहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, अभी पुलिस की ओर से इस संबंध में पुष्टि की जा रही है।

एक जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, धाराओं में आएगा बदलाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। यानी अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इन तीनों कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है जोकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों पर चल रही थी, इससे छुटकारा मिल सकेगा. इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त किया गया है। इसमें राज्य के खिलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शामिल किया गया है।

बड़ा फैसला : हरियाणा के किसानों को अब कभी नहीं देना होगा आबियाना, 4299 गांवों के किसानों को होगा लाभ

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पिछले साढ़े 9 सालों में हरियाणा के किसानों के हितों व उनके कल्याण के प्रति वचनबद्धता का परिचय देते हुए मनोहर सरकार ने नित नई-नई योजनाएं चलाकर किसानों का उत्थान किया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हितों में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्रिटिश शासन के समय से किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला आबियाना समाप्त करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2024-25 के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहाकि 1 अप्रैल, 2024 से नहरी पानी की आपूर्ति पर प्रदेश में किसानों से लिया जाने वाला आबियाना बंद किया जाएगा। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 4299 गांवों के किसानों को 140 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ होगा। साथ ही, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत भी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी भी आबियाना को खत्म नहीं किया गया है। साल दर साल यह आबियाना चलता आ रहा था। पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने आबियाना बंद करने का कदम उठाया है।

इस ऐतिहासिक फैसले से सरकार ने ब्रिटिश शासन से चली आ रही परंपरा को खत्म करते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार, प्रमुख जिलों की सूची में जिला हिसार में 349 गांवों के 31.23 करोड़ रुपये का आबियाना बकाया है।

इसी प्रकार, कैथल के 320 गांवों के 19.90 करोड़ रुपए, भिवानी के 417 गांवों के 17.13 करोड़ रुपए, सिरसा के 395 गांवों के 12.48 करोड़ रुपए, झज्जर के 157 गांवों के 6.94 करोड़ रुपए, चरखी दादरी के 229 गांवों के 6.09 करोड़ रुपए और नूहं के 171 गांवों के 5.98 करोड़ रुपए का आबियाना बकाया है। सरकार के फैसले से अब इन गांवों के किसानों को आबियाना नहीं देना होगा।

सिंचाई के लिए 16,932 आउटलेट निर्धारित हैं और आबियाना की इस बकाया राशि के अंतर्गत लगभग 24.11 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जिसमें रबी फसलों के तहत 12.19 लाख हेक्टेयर और खरीफ फसलों के तहत 11.92 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। आबियाना खत्म होने से अब किसानों को सीधे तौर पर लगभग 140 करोड़ रुपये का लाभ होगा।